नईदुनिया



व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक नेता ने अमेरिका की जीत का ऐलान किया, व्हाइट हाउस ने कहा, ऐसा हुआ तो बहुत पछतावा करेंगे मतदाता

न्यूयार्क/वाशिंगटन (अमेरिका)

अमेरिकी हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक अल्पमत के नेता हकीम जेफरीज ने अमेरिका की जीत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आए अनुमानों से पता चलता है कि कांग्रेस के निचले सदन पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो जाएगा। हाउस में डेमोक्रेट्स के नियंत्रण की खबरों के बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा हुआ तो डेमोक्रेट्स को वोट देने वाले मतदाता पछतावा करेंगे।

जेफरीज ने एक्स पर कहा, अमेरिका की जीत! विश्लेषणात्मक सेवा डिसीजन डेस्क एचक्यू और ब्राडकास्टर सीएनएन व एनबीसी के अनुमानों के अनुसार, कांग्रेस चुनावों के नतीजों के आधार पर अमेरिकी हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो जाएगा। फिलहाल, दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी के पास मामूली बहुमत है। हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन के पास 218 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 214 सीटें हैं। वहीं सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं और डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें हैं।

इस बीच व्हाइट हाउस ने बताया कि जिन अमेरिकियों ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया है, उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। ऐसा तब होगा जब ईरान के साथ चल रहा विवाद सुलझ जाएगा और पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन उनके पास अभी भी कट्टर उदारवादी डेमोक्रेट्स की सूची ही रह जाएगी। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया, आज जिन लोगों ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया है, उन्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। जब ईरान विवाद सुलझने के बाद पेट्रोल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी, तब उन्हें एहसास होगा कि वे कट्टर उदारवादी डेमोक्रेट्स के साथ फंस गए हैं।

यह टिप्पणी अमेरिकी विश्लेषक फर्म डिसीजन डेस्क एचक्यू के उस अनुमान के बीच आई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो जाएगा। तीन नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यावधि कांग्रेसनल चुनाव हुए, जिसमें अमेरिकियों ने प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और 35 सीनेटरों के लिए वोट डाला।

इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के एक प्रतिनिधि ने संकेत दिया है कि अमेरिकी कांग्रेसनल चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद भी व्हाइट हाउस का रुख अडिग (यानी हार न मानने वाला) बना हुआ है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी विश्लेषक सेवा डिसीजन डेस्क एचक्यू ने कहा था कि शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इस बात की 84% संभावना है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण रिपब्लिकन के हाथों से निकलकर डेमोक्रेट्स के पास चला जाएगा। डेमोक्रेट्स की जीत के अनुमान के बीच, व्हाइट हाउस के भीतर के माहौल को लेकर एजेंसी के एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, व्हाइट हाउस का रुख अडिग है।

न्यूज ब्रीफ

ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री बालफोर के कुछ शब्दों ने बदल दी मिडिल ईस्ट की तकदीर



लंदन। किसे पता था कि एक छोटा सा दस्तावेज मिडिल ईस्ट की नियति बदलने वाला साबित होगा। यह ब्रिटिश सरकार का एक साधारण सा टाइप किया हुआ पत्र था, जिसमें लिखे मात्र 67 शब्दों ने ही आने वाली पूरी सदी के लिए पश्चिम एशिया की किस्मत तय करके रख दी। यह ऐतिहासिक दस्तावेज, जिसे बालफोर घोषणापत्र के नाम से जाना जाता है, आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से जारी संघर्ष की जड़ों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर, 1917 को ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री आर्थर बालफोर ने ब्रिटिश यहूदी समुदाय के प्रमुख नेता लार्ड वाल्टर रोथ्सचाइल्ड को एक पत्र भेजा। इसी पत्र को इतिहास में बालफोर घोषणापत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटेन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन की धरती पर यहूदियों के लिए अपना एक घर बनाने के विचार का समर्थन किया था। इस छोटे से पैराग्राफ में ब्रिटेन का वादा छुपा था, जिसने यहूदी देश यानी जायोनिस्ट मूवमेंट के विचार को दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक महाशक्ति ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन दिला दिया था। पत्र में लिखा था- ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करती है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने हर संभव प्रयास करेगी।

नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों पर सख्त चीन



बीजिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते दखल और इसके कारण श्रम बाजार पर मंडराते बेरोजगारी के खतरे से निपटने के लिए चीन सरकार ने एक महत्वाकांक्षी 18 सूत्रीय प्लान लागू किया है। स्टेट काउंसिल के जनरल आफिस की ओर से जारी इन सख्त दिशा-निर्देशों के तहत देश की सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने यहां किसी भी एआई प्रणाली को अपनाने से पहले कर्मचारियों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का पूरा आकलन करें। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य देश के तकनीकी विकास माडल को रोजगार के अनुकूल बनाए रखना है, ताकि आटोमेशन के इस दौर में आम नागरिकों की आजीविका सुरक्षित रह सके। इस व्यापक कार्ययोजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अनइम्प्लायमेंट बफर पीरियड की व्यवस्था है, जिसके तहत यदि कोई कंपनी बड़े पैमाने पर एआई या आटोमेशन लागू करती है, तो उसे कर्मचारियों को अचानक नौकरी से हटाने की अनुमति नहीं होगी। प्रबंधन को अपने कर्मियों को समय रहते आगाह करना होगा, उन्हें नई तकनीक सीखने के अवसर देने होंगे और कंपनी के भीतर ही अन्य विभागों में उनकी पुनः तैनाती की योजना तैयार करनी होगी। यदि आंतरिक रूप से समायोजन संभव न हो, तो कंपनियों को कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने में भी सक्रिय सहायता प्रदान करनी होगी। इन गाइडलाइंस में विशेष तौर पर उन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है जहाँ श्रम बल की अधिकता है, जैसे कि टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर।

कमजोर होती मांसपेशियों की असली वजह अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खोज ली



कोपेनहेगन। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उम्र के साथ मांसपेशियों के कमजोर होने के पीछे एक छिपी हुई प्रक्रिया का पता लगाया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के नए शोध से यह सामने आया है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियां कोशिकाओं को डैमेज से बचाने के लिए अपनी ताकत से समझौता करती हैं। चूहों पर किए गए इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि एक अणु को आंशिक रूप से बहाल करने से मांसपेशियों के क्षय के लक्षणों को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इससे भविष्य में उम्र से संबंधित मांसपेशियों की कमजोरी के उपचार की नई उम्मीदें जाग गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे शरीर के मांसपेशी ऊतक में अलग-अलग तरह के तंतु होते हैं। ये बहुत शक्तिशाली और तेज गति पैदा करते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है और माइटोकान्ड्रिया की कार्यक्षमता भी कमजोर होने लगती है। हैरानी की बात यह है कि उम्र ढलने के साथ मांसपेशियां ऐसे धीमी गति वाले रेशों की तरफ बढ़ने लगती हैं जो उन्हीं कमजोर माइटोकान्ड्रिया पर ज्यादा निर्भर होते हैं।

बालेन्द्र सरकार अपनी ही पार्टी के निर्देशों की कर रहे अनदेखी, आंतरिक विवाद में घिरी आरएसपी

काठमांडू

नेपाल की बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में रही सरकार द्वारा अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के द्वारा दिए गए निर्देशों और नीतियों की पालन करने में आनाकानी और अनदेखी करने से सरकार और पार्टी के बीच दूरी बढ़ती हुई दिख रही है।

सत्तारूढ़ आरएसपी ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बार-बार अपनी चिंताएं रखी हैं और कई बार चेतावनी के साथ निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन पार्टी की इन मांगों और हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर अनसुना किया गया है। पार्टी ने लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ मानी जाने वाली गतिविधियों पर चिंता जताई है। हालांकि, पीएम शाह ने पार्टी के इन निर्देशों की हमेशा ही अनदेखी की है।

गत 13 जुलाई को मीडिया संस्थानों, कारोबारी प्रतिष्ठानों और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के आवास के सामने वाहन खड़े कर रास्ता बाधित किया गया था। बताया गया कि इस घटना में सरकार से जुड़े लोग शामिल थे।

मीडिया संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर वाहन खड़े किए जाने की खबरें सामने आने के तुरंत बाद आरएसपी के महासचिव बिपिन आचार्य ने बयान जारी कर सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया। उन्होंने मीडिया संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर वाहन खड़े कर रास्ता रोकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।

आनलाइन खबर, हिमालय टेलीविजन और कान्तिपुर जैसे बड़े मीडिया संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर कथित तौर पर सरकार के करीबी लोगों ने वाहन खड़े किए थे। प्रधानमंत्री शाह के करीबी लोगों ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि यह पासपोर्ट विभाग के सामने गणेश नेपाली द्वारा आत्मदाह किए जाने के बाद मीडिया संस्थानों की खुले स्थानों पर पार्किंग के समर्थन में अपनाई गई स्थिति के जवाब में किया गया था।

प्रधानमंत्री के करीबी लोगों ने जहां रास्ता बाधित करने की कार्रवाई को सही ठहराया, वहीं पार्टी ने इसका विरोध किया। आचार्य ने कहा कि स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की जीवनरेखा है।

बयान में कहा गया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इसलिए पार्टी प्रेस को



डराने-धमकाने के उद्देश्य से की गई इन और ऐसी किसी भी अन्य कार्रवाई की निंदा करती है।

आरएसपी ने कहा कि राज्य के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को निर्भीक होकर काम करने के लिए आवश्यक वातावरण को कमजोर करने के उद्देश्य से की जाने वाली संदिग्ध और अस्पष्ट गतिविधियां लोकतांत्रिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन हैं।

मीडिया के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता जताते हुए आरएसपी ने सरकार से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

बयान में कहा गया, हम नेपाल सरकार, गृह मंत्रालय और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों का गंभीर ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि वे मीडिया संस्थानों की भौतिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की तत्काल पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

पार्टी के हस्तक्षेप के बावजूद पीएम बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस घटना की जांच करने या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री शाह के मुख्य सलाहकार कुमार बेन और गृह मंत्री सुदन गुरुङ के करीबी लोग भी कथित तौर पर मीडिया संस्थानों के रास्ते रोकने के लिए वाहन खड़े करने में शामिल थे।

मीडिया संस्थानों द्वारा वाहन मालिकों की पहचान कर अधिकारियों को जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

पिछले सप्ताह भी यही स्थिति दोहराई गई, जब सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया संस्थानों में प्रवेश कर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। नेपाल प्रेस के पत्रकार विश्वमणि सुबेदी को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। पुलिस ने नया पत्रिका के कार्यालय में भी बिना गिरफ्तारी वारंट के उसके एक पत्रकार को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी। 30 अक्टूबर को पुलिस ने मोटिवेट न्यूज के संपादक शोभराज बराल और डीएनए खबर के प्रधान संपादक धीरज बस्नेत को गिरफ्तार किया। इस घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया और भी गैरजिम्मेदाराना रही। प्रधानमंत्री सचिवालय ने मामले से शाह को अलग करते हुए कहा कि उन्हें पत्रकारों की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी। वहीं, पुलिस प्रशासन ने दावा किया कि पत्रकारों को प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हिरासत में लिया गया था। आरएसपी ने पत्रकारों की गिरफ्तारी और सुरक्षा कर्मियों के मीडिया संस्थानों में प्रवेश पर तत्काल आपत्ति जताई। 30 अक्टूबर को पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट जारी कर पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। पार्टी ने सचिवालय की आपात बैठक भी बुलाई। बैठक में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराते हुए सरकार को घटना की जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

कब्रें तैयार करने का प्रशिक्षण ले रही अमेरिकी सेना, बड़े और घातक युद्ध की आशंका



वाशिंगटन

अमेरिकी सेना ने एक ऐसी असामान्य तैयारी शुरू कर दी है जिसकी आवश्यकता कोरियाई युद्ध के बाद से इतने बड़े पैमाने पर कभी महसूस नहीं की गई थी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार अमेरिकी सेना अब युद्ध के मैदान में भारी संख्या में सैनिकों के हताहत होने की स्थिति में सामूहिक अस्थायी कब्रें तैयार करने का विशेष प्रशिक्षण ले रही है। इसके लिए बुलडोजर, भारी खुदाई करने वाली मशीनों और इंजीनियरिंग यूनिट्स को मैदान में उतारा गया है। इराक और अफगानिस्तान जैसे पिछले सैन्य अभियानों में इस स्तर पर कब्रों की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी थी।

करीब सात दशक बाद शुरू हुए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध में अत्यधिक जनहानि की स्थिति में सैनिकों के शवों को सुरक्षित रखना, उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और संघर्ष थमने के बाद उन्हें उनके परिवारों तक सम्मानजनक तरीके से पहुंचाना है। हाल ही में अमेरिकी सेना की थर्ड कोर सस्टेनमेंट कमांड और इंजीनियर टीमों ने एक कड़ा अभ्यास पूरा किया, जिसमें नकली अवशेषों और भारी मशीनों का उपयोग करके लंबी खाइयां खोदी गईं। इस दौरान यह आकलन किया गया कि एक इंजीनियर कंपनी बिना रुके काम करते हुए चौबीस घंटे के भीतर चौबीस सौ शवों के लिए अस्थायी कब्रें तैयार कर सकती है। इस प्रशिक्षण में दो दशकों में पहली बार सेना के पादरियों को भी शामिल किया गया ताकि युद्ध के मैदान में बिना किसी विलंब के धार्मिक संस्कारों के साथ जमीन को पवित्र किया जा सके। यह अचानक उठाया गया कदम वैश्विक भू-राजनीतिक हालात में आए गंभीर बदलावों और भविष्य के बड़े संघर्षों की आशंका का स्पष्ट संकेत देता है। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि यदि चीन, रूस या ईरान जैसी महाशक्तियों के साथ कोई सीधा और बड़ा महायुद्ध छिड़ता है, तो युद्ध के शुरुआती दौर में ही हजारों सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। ऐसी भीषण परिस्थितियों में हवाई क्षेत्र के बंद होने या परिवहन विमानों की भारी कमी के कारण हजारों शवों को तुरंत स्वदेश वापस भेजना असंभव साबित होगा। युद्ध क्षेत्र में शवों को डीकंपोज होने और संक्रामक बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उनकी पहचान दर्ज कर उन्हें सुरक्षित रूप से अस्थायी तौर पर दफनाया जाए, ताकि युद्ध समाप्ति के बाद उन्हें निकालकर स्वजनों को सौंपा जा सके।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमांडू पहुंचे



काठमांडू। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं। वह कुछ देर पहले त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। विदेश सचिव की नेपाल यात्रा को प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के आगामी भारत दौरे की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री शाह की भारत यात्रा की तैयारी और दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनका दौरा हो रहा है। काठमांडू पहुंचे मिस्री उच्चस्तरीय मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। उनकी प्रधानमंत्री शाह से भी मुलाकात तय है। उनका विदेशमंत्री शिशिर खनाल, वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बैठक में नेपाल-भारत द्विपक्षीय संबंधों, आपसी सहयोग और प्रधानमंत्री शाह की संभावित भारत यात्रा के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दौरा पूरा करने के बाद भारतीय विदेश सचिव मिस्री कल स्वदेश रवाना होंगे।

अमेरिकी विमानवाहक पोतों के लिए संकटकारी है चीनी मिसाइल

बीजिंग

चीन की डीएफ-26बी कैरियर किलर मिसाइल एक बार फिर वैश्विक रक्षा हलकों में चर्चा का केंद्र बन गई है, जब इसका एक नया वीडियो सामने आया जिसमें इसे रेगिस्तान में बने एक बड़े जहाज जैसे ढांचे पर हमला करते हुए दिखाया गया है। डीएफ-26 परिवार का हिस्सा यह मिसाइल जमीन से लान्च की जाती है और इसकी मारक क्षमता करीब 4,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों और विमानवाहक पोतों-जैसे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जार्ज वाशिंगटन और यूएसएस लिंकन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है।

मोबाइल लान्चर से दागे जाने की क्षमता और पारंपरिक व परमाणु दोनों तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम होने के कारण दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और इसे रोकना बेहद कठिन माना जाता है। रूसी विशेषज्ञों तक का दावा है कि यह मिसाइल अमेरिकी विमानवाहक पोतों को गंभीर क्षति



पहुंचाने में सक्षम है।

हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रेगिस्तान में किसी स्थिर ढांचे को निशाना बनाना और खुले समुद्र में लगातार गतिमान एक लाख टन वजनी विमानवाहक पोत को भेदना दो अलग-अलग बातें हैं। इसके लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट निगरानी, रडार सिस्टम और मैनुवरेबल री-एंट्री व्हीकल जैसी उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है, जो मिसाइल को अंतिम चरण में दिशा बदलने में मदद करे। इसके मुकाबले अमेरिकी नौसेना के पास भी अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एजिस युद्ध प्रबंधन सिस्टम और एस.एम.-3 व एस.एम.-6 जैसी उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस डिस्ट्रायर, क्रूजर और पनडुब्बियों का मजबूत सुरक्षा घेरा मौजूद है। इस मिसाइल का मुख्य सामरिक महत्व केवल किसी जहाज को डुबोने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक उद्देश्य अमेरिकी विमानवाहक पोतों को चीन के समुद्री तटों के करीब आने से रोकना है। लंबी दूरी की इन एंटी-शिप मिसाइलों के निरंतर खतरे के कारण अमेरिकी नौसेना को अपनी तैनाती की रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है और उन्हें चीनी तटों से अधिक दूरी पर रहना पड़ सकता है, जिससे उनके लड़ाकू विमानों की प्रभावी सीमा प्रभावित होगी। यह मिसाइल अमेरिका की पारंपरिक समुद्री ताकत को चुनौती देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना सामरिक दबदबा बढ़ाने की चीन की व्यापक सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बांग्लादेश की राजधानी में औद्योगिक अशांति, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, झड़प, 100 घायल, 40 गिरफ्तार

ढाका (बांग्लादेश)

देश की राजधानी के मीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों की 30,000 टका न्यूनतम वेतन करने की मांग को लेकर तीन दिन से चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच दिनभर तीखी झड़पें हुईं। शाम होते-होते धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि इन झड़पों में 100 लोग घायल हुए हैं। घायलों में पुलिस कर्मचारी भी हैं। अशांति फैलाने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा उद्योग कर्मचारियों और मजदूरों ने सरकार के आंदोलन के पीछे किसी राजनीतिक उकसावे या बड़ी साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई के चलते वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। पुलिस ने अशांति भड़काने के आरोप में देररात 40 लोगों को



गिरफ्तार करने की जानकारी दी। पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल हो गए हैं।

प्रदर्शनकारी शोएब इस्लाम ने कहा कि तोड़फोड़ या हिंसा में मजदूरों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, हम मजदूर किसी भी तरह की तोड़फोड़ में शामिल नहीं हैं। अगर कोई ऐसा करता है, तो यह पुलिस का काम है कि वह इस पर कार्रवाई करे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी वजह के हमला किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके साथियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है, तो मजदूर इसका विरोध करेंगे। एक अन्य मजदूर शेफली बेगम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि इन प्रदर्शनों के पीछे बाहरी समूहों का हाथ है। उन्होंने कहा, हमें किसी ने उकसाया नहीं है। हम अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी शमीम ने कहा कि अगर सरकार मांगी गई न्यूनतम वेतन राशि की घोषणा कर दे, तो ये प्रदर्शन तुरंत खत्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार 30,000 टका न्यूनतम वेतन की घोषणा कर देती है, तो सभी मजदूर अपनी फैक्ट्रियों में लौट जाएंगे और कोई भी सड़क पर नहीं रहेगा। वहीं, कानून लागू करने वाले अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनों में ऐसे लोग घुस आए हैं, जिनका मजदूरों की वेतन मांगों से कोई लेना-देना नहीं है।

ढाका रेंज के डीआईजी मो. मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि ढाका, मीरपुर, गाजीपुर और नारायणगंज में हुई अशांति के सिलसिले में पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कोई भी कपड़ा कारखाने का मजदूर नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस सबूत जुटा रही है ताकि हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके।

ढाका जिला पुलिस अधीक्षक शमीमा परवीन ने यह भी आरोप लगाया कि बुरका और हेलमेट पहने कुछ लोग देश को अस्थिर करने की कोशिश में मजदूरों को उकसा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के पास इन गतिविधियों की फंडिंग के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसके समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया।